www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 274 | जौनपुर सोमवार, 25 मई 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

वंदे मातरम गाने से खत्म हो जाएगा मदरसों से आतंकवाद : नितेश राणे

मुंबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने विपक्ष और अवैध प्रवासियों पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने मुंबई में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान और मदरसों में श्वंदे मातरमश अनिवार्य को सही बताया है। मुंबई में जारी अतिक्रमण हटाओ अभियान पर मीडिया से बात करते हुए मंत्री नितेश राणे ने साफ किया कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, ष्अगर आप सरकारी जमीन पर अवैध घर या मस्जिदें बनाएंगे तो हम उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। यह सरकार की जमीन है, किसी की निजी जागीर नहीं।ष्राणे ने कहा कि हमने चुनावों के दौरान ही जनता से वादा किया था कि राज्य में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की अवैध मौजूदगी को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। बांद्रा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, हम अपना वादा निभा रहे हैं। सिर्फ बांद्रा ही नहीं, बल्कि कई अन्य जगहों पर भी पूरी तरह सफाई की जरूरत है। सभी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या अपना बोरिया–बिस्तर समेटकर यहां से चले जाएं।ष लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी पर मंत्री राणे ने बेहद कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, ष्अगर कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करता है, तो वह केवल पाकिस्तान का एजेंट ही हो सकता है।

जुबान फिसलने और मीम्स पर रवि किशन ने दी प्रतिक्रिया

मुंबई, (एजेंसी)। सोशल मीडिया के दौर में सावधानी कितनी भी बरती जाए, लेकिन छोटी–सी चूक भी पल भर में वायरल हो जाती है। अक्सर इसका खामियाजा बड़ी शख्सियतों को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही अभिनेता और सांसद रवि किशन के साथ हुआ। हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान जुबान फिसलने के बाद सोशल मीडिया पर उनके कई मीम्स बने, जिस पर उन्होंने फिल्म 'मां बहन' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में प्रतिक्रिया दी। रवि किशन ने बताया कि उन्हें इस बात का जरा–सा भी अंदाजा नहीं था कि इंटरनेट पर आखिर कौन–सी चीज उन्हें वायरल बना देती है।ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान जब अभिनेता से उनकी जुबान फिसलने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मीडिया से कहा, "मैं सच में दिल से और महादेव की कसम खाकर कहता हूं कि मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं क्यों वायरल हो जाता हूं। अभी हाल ही में मैंने 'वर्क फ्रॉम होम' की जगह गलती से 'होम फ्रॉम वर्क' बोल दिया था। उससे कुछ समय पहले, जब मैं संसद जा रहा था, तब मैंने श्द लेटश की जगह श्जल्दी द लेटश कह दिया था।ष उन्होंने आगे कहा, "आखिर मैं भी इंसान ही हूं। ऐसी गलतियां होती रहती हैं और शायद आगे भी होती रहेंगी। लोग मुझे ऐसे क्यों देखते हैं, जैसे मैं कोई इंसान नहीं हूं या किसी अलग दुनिया से आया हूं?"

भारत पर बढ़ा दुनिया का भरोसा, युवा शक्ति और टेक्नोलॉजी बनी पहचान - पीएम मोदी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 19वें रोजगार मेले के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित युवाओं को 51 हजार से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया भारत के युवाओं, भारत की टेक्नोलॉजी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर बेहद उत्साहित है। उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया का भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बनकर उभर रहा है और इसका सबसे बड़ा लाभ देश के युवाओं को मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हालिया 5 देशों के दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि यह यात्रा सिर्फ पांच देशों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इस दौरान दुनिया भारत के विकास और भारतीय युवाओं की क्षमता को लेकर बेहद आशावादी है। उन्होंने कहा कि

की कई बड़ी कंपनियों और वैश्विक नेताओं के साथ उनकी विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हर जगह एक बात समान रूप से महसूस हुई कि आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है और भारत भी विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है ताकि देश के युवाओं को रोजगार, नए अवसर और ग्लोबल एक्सपोजर मिल सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीदरलैंड के साथ सेमीकंडक्टर, जल प्रबंधन, कृषि और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में अहम चर्चा हुई है। वहीं स्वीडन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और डिजिटल इनोवेशन पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। उन्होंने आगे बताया कि नॉर्वे के साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी और मैरीटाइम सेक्टर में सहयोग को आगे बढ़ाया गया है। इसके अलावा यूएई के साथ स्ट्रैटेजिक एनर्जी और टेक्नोलॉजी पार्टनर्शिप को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं।

हमें स्वस्थ श्रीकाकुलम के लिए तैयार रहना चाहिए : राममोहन नायडू

श्रीकाकुलम, (एजेंसी)। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी की फिट इंडिया पहल से प्रेरित होकर सभी से श्स्वस्थ श्रीकाकुलमश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया। भारतीय संस्कृति ब्लॉग येरन्ना क्रीड़ा उत्सवम कार्यक्रम के अंतर्गत, उन्होंने शुक्रवार को श्रीकाकुलम शहर के कारगिल पार्क में एमपी कप 2026 बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। उन्होंने टूर्नामेंट का लोगो जारी किया और खिलाड़ियों से बड़ी संख्या में भाग लेने का आह्वान किया। उद्घाटन के दौरान, केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू, श्रीकाकुलम विधायक गोंडू शंकर, प्रभारी कलेक्टर फरमान अहमद खान और एसपी महेश्वर रेड्डी ने टीमें बनाकर एक दोस्ताना मैच खेला। केंद्रीय मंत्री ने लगभग एक घंटे तक क्रिकेट खेला, जिससे उपस्थित लोगों में उत्साह बढ़ा। राममोहन नायडू ने कहा कि एमपी कप बॉक्स क्रिकेट टूर्नामेंट इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को मोबाइल फोन छोड़कर शारीरिक व्यायाम पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के श्फिट इंडियाश नारे से प्रेरित होकर, हम सभी को श्फिट श्रीकाकुलमश के लिए तैयार रहना चाहिए।उन्होंने आज के युवाओं को सलाह दी कि वे अपने दैनिक जीवन में कम से कम एक खेल को अपनाएं। उन्होंने आगे कहा कि विकास के लिए सभी का स्वस्थ होना आवश्यक है, और खेल और व्यायाम इसमें सहायक होते हैं।

पर्यावरण सुधार के लिए हर स्तर पर काम कर रही दिल्ली सरकार : रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण और बेहतर पर्यावरण के लिए 360 डिग्री पर काम कर रही है। चाहे वायु प्रदूषण की समस्या हो या फिर अधिक से अधिक पौधरोपण, सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि दिल्ली का पर्यावरण बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण सिर्फ दो महीनों की चुनौती नहीं है बल्कि यह एक ऐसा काम है जिसे पूरे साल करना होता है। इसके लिए हमारी सरकार दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और प्रदूषण को ठीक करने पर गंभीरता से काम कर रही है। कई नई पहल की जा रही हैं। सीएम ने कहा कि आप सभी को याद होगा कि दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने स्टार्टअप्स की एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी आयोजित की थी, जहां लोग पर्यावरण को बेहतर बनाने और प्रदूषण को खत्म करने के लिए नए, इनोवेटिव आइडिया लेकर आए थे। हमने उन्हें प्रदर्शित किया और आईआईटी दिल्ली के सहयोग से हमने उनका मूल्यांकन किया। हमने उनमें से सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स को चुना और अब हम उन्हें दिल्ली में लागू कर रहे हैं।

श्रमिकों का सम्मान और सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : सीएम योगी

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिक कल्याण, कौशल विकास और रोजगार सृजन को और व्यापक तथा परिणाममुखी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने बाल श्रमिक विद्या योजना को प्रदेश के सभी 75 जनपदों में विस्तारित करने, 'सेवामित्र व्यवस्था' को और प्रभावी बनाने, निर्माण श्रमिकों के लिए बड़े शहरों में आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र विकसित करने तथा रोजगार मिशन को वैश्विक अवसरों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। शनिवार को श्रम एवं सेवायोजन विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी बच्चा आर्थिक मजबूरी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाल श्रम प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर बच्चों को विद्यालयों से जोड़ा जाए और उनके पुनर्वास की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के सहयोग से इन बच्चों के कौशल विकास की कार्ययोजना भी तैयार की जाए। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2020 में प्रारंभ की गई इस योजना के तहत 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के कामकाजी बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में योजना 20 जनपदों में संचालित है। मुख्यमंत्री ने इसे नए प्रावधानों के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 'सेवामित्र व्यवस्था' को रोजगार और जनसुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए।

बंगाल में घुसपैठ रोकने के लिए चल रहे एक्शन के लिए अमित शाह ने थपथपाई शुभेन्दु की पीठ

बंगाल, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद अब दिल्ली और कोलकाता के रिश्तों में एक नया मोड़ दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद शुभेन्दु अधिकारी की पहली दिल्ली यात्रा ने साफ कर दिया है कि बंगाल को अब केंद्र से टकराव नहीं, बल्कि तालमेल और तेज विकास की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से हुई मुलाकातों की श्रृंखला ने बंगाल की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए नए संकेत दे दिए हैं। सबसे बड़ा फैसला केंद्र सरकार की ओर से आया, जब जल संसाधन मंत्रालय की योजनाओं के लिए बंगाल को उनतालीस हजार करोड़ रुपये जारी करने पर सहमति बनी। यह राशि ऐसे समय में आई है जब राज्य लंबे समय से आर्थिक सुस्ती, अधूरी परियोजनाओं और केंद्र राज्य टकराव की राजनीति से जूझ रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी को भरोसा दिया कि बंगाल के आर्थिक विकास, औद्योगिक पुनर्जीवन और रोजगार सृजन के लिए केंद्र हर संभव सहयोग देगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद शुभेन्दु अधिकारी ने साफ कहा कि बंगाल को अब विकास की तेज रफ्तार पर लाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने दोहराया कि राज्य में अब पारदर्शी शासन, तेज फैसले और दोहरे इंजन की सरकार के जरिए नई व्यवस्था स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने भी सबका साथ, सबका विकासष के मंत्र को दोहराते हुए बंगाल को केंद्र की प्राथमिकता बताया। दिल्ली दौरे का सबसे संवेदनशील पहलू बांग्लादेश सीमा और घुसपैठ का मुद्दा रहा। गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई लंबी बैठक में सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ पर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार शाह ने राज्य सरकार को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं ताकि सीमा पार से होने वाली घुसपैठ पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

ईंधन कीमतों पर भड़के तेजस्वी यादव, बोले– जनता को झेलनी पड़ेगी महंगाई

पटना, (एजेंसी)। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के मूल्य वृद्धि को लेकर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में जनता को भयंकर महंगाई झेलनी पड़ेगी। उन्होंने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि मोदी सरकार ने आज फिर सीएनजी, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। एनडीए सरकार ने पिछले 10 दिनों में तेल की कीमतों में लगभग 5 रुपए की वृद्धि की है, यानि 50 पैसे प्रतिदिन। अभी और बढ़ना शेष है। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार को सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर लिखा, ष्जब क्रूड ऑयल सस्ता था, तब भी ये आपकी जेब काटकर निजी कंपनियों को मुनाफा दिला रहे थे और अब भी। जो भाव कच्चे तेल का 2014 में था, अब उससे भी बहुत कम है, लेकिन पेट्रोल–डीजल के दाम दुगुना हो गए हैं।ष उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में जनता को भयंकर महंगाई झेलनी पड़ेगी, प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां जाएंगी, प्रवासी श्रमिक वापस लौटेंगे, लघु उद्योग–धंधे कम होंगे, गरीबी–बेरोजगारी बढ़ेगी। सरकार को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि नफरत का कारोबार, भाषणबाजी, रील्स और एंटरटेनमेंट के लिए जिसे चुना था, वो श्फुल इंटरटेनमेंटश मिलता रहेगा। नौकरी, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, कृषि, गांव–किसान, शिक्षा–स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था इत्यादि पर गहन विचार–विमर्श और ध्यान केंद्रित देने की बजाय इनका फोकस संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग, हेडलाइन मैनेजमेंट, हिंदू–मुस्लिम, मंदिर–मस्जिद, गाय–गोबर और स्थलों के नाम बदलने पर रहेगा।

निजी स्कूल सत्र शुरू होने से पहले बिना सरकारी मंजूरी बढ़ा सकते हैं फीस

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में बिना सरकारी मदद वाले प्राइवेट स्कूल नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में फीस बढ़ा सकते हैं। इसके लिए उन्हें शिक्षा निदेशालय (डीओई) की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर स्कूल नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में फीस बढ़ाता है, तो उसे सिर्फ शिक्षा निदेशालय को सूचना देनी है, उन्हें अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि अगर स्कूल शैक्षणिक सत्र के बीच में फीस बढ़ाना चाहते हैं, तब शिक्षा निदेशालय की मंजूरी जरूरी होगी।कोर्ट ने अभिभावकों को राहतदेते हुए यह भी कहा कि स्कूल पुराने सालों की बढ़ी हुई फीस का बकाया अब नहीं वसूल सकते। यानी 2016–17 या पुराने सत्रों की बढ़ी फीस अब अभिभावकों से नहीं मांगी जा सकती। स्कूलों की आखिरी प्रस्तावित फीस वृद्धि अब अप्रैल 2027 से ही लागू होगी। कोर्ट ने शिक्षा निदेशालय के उन सभी आदेशों को रद्द कर दिया, जिनमें शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में फीस बढ़ाने के प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने निदेशालय के पास पेंडिंग फीस बढ़ाने के प्रस्तावों को भी बंद कर दिया।कोर्ट ने निदेशालय के उस अंतर को भी खारिज कर दिया जो श्लैंड क्लॉजश (जमीन से जुड़ी शर्त) के तहत आने वाले स्कूलों और ऐसे क्लॉज के तहत न आने वाले स्कूलों के बीच किया गया था। कोर्ट ने कहा कि लैंड क्लॉज, जो आमतौर पर अलॉटमेंट लेटर में एक शर्त होती है, उसे एक्ट और नियमों के दायरे में ही काम करना चाहिए और वह निदेशालय की कानूनी शक्तियों को बढ़ा नहीं सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश कई प्राइवेट स्कूलों की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया। इन स्कूलों ने फीस बढ़ाने के प्रस्ताव को शिक्षा निदेशालय की ओर से नामंजूर किए जाने के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। स्कूलों का कहना था कि शिक्षा निदेशालय बार–बार उनकी फीस बढ़ाने की मांग ठुकरा रहा था, जिससे स्कूलों की आर्थिक स्वतंत्रता प्रभावित हो रही है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नीट परीक्षार्थियों को मुफ्त बस यात्रा का बड़ा तोहफा

पटना, (एजेंसी)। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीट परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों छात्र–छात्राओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने राज्य में सभी नीट परीक्षार्थियों के लिये बस यात्रा को मुफ्त कर दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म श्एक्सश पर पोस्ट कर बताया कि परीक्षा के लिए बिहार की सभी सरकारी बसों में यात्रा पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। उन्होंने लिखा, ष्नीट परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए, बिहार राज्य की सभी सरकारी बसों में यात्रा निःशुल्क रहेगी। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन, राज्य के सभी मठों एवं मंदिरों तथा गैर–सरकारी संगठनों से अनुरोध है कि वे बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों और अन्य प्रमुख स्थानों पर परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों के लिए पेयजल, सत्तू आदि की व्यवस्था करने में सहयोग प्रदान करें।ष इसके अलावा उन्होंने परीक्षा के लिए सभी उम्मीदवारों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं। सीएम सम्राट चौधरी की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब देशभर में नीट यूजी परीक्षा की तैयारी जोरों पर है। बिहार से बड़ी संख्या में छात्र–छात्राएं इस परीक्षा में भाग लेते हैं। कई छात्र दूरदराज के जिलों से पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया जैसे परीक्षा केंद्रों पर आते हैं। ऐसे में परिवहन खर्च उनकी चिंता का बड़ा विषय होता है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से अभिभावकों और छात्रों दोनों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने केवल बस यात्रा निःशुल्क करने तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि पूरे प्रशासन को परीक्षार्थियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय होने का संदेश दिया है। उन्होंने जिला प्रशासन को बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशनों पर पेयजल, सत्तू, छाछ जैसी पौष्टिक पेय पदार्थों की व्यवस्था करने के लिए कहा है। साथ ही राज्य के प्रसिद्ध मठ–मंदिरों और एनजीओ से भी सहयोग की अपील की गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, सभी जिला मजिस्ट्रेटों को इस संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

संपादकीय

जस्टिस शरण की आपत्ति

एनएचआरसी के बारे में जस्टिस श्रीधरन की टिप्पणी इस धारणा की पुष्टि करती है कि संवैधानिकध्वैधानिक संस्थाएं अपना काम करने के बजाय किसी राजनीतिक परियोजना से संचालित हो रही हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 588 मदरसों पर लगे आरोप की जांच करने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार को दिया। इल्जाम है कि ये मदरसे राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से अनुदान हासिल करते हैं, लेकिन इमारत, फर्नीचर, हॉस्टल आदि के मामलों में बुनियादी शैक्षिक मानदंडों का पालन नहीं करते। एनएचआरसी के इस आदेश को टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया और अन्य कई पक्षों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। वहां न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति विवेक शरण की बेंच ने एनएचआरसी के आदेश पर रोक लगा दी। लेकिन निर्णय सुनाने के क्रम में उन्होंने जो टिप्पणियां कीं, उनसे उनके मतभेद जाहिर हुए। जस्टिस शरण का कहना था कि चूंकि एनएचआरसी की तरफ से कोर्ट में कोई मौजूद नहीं हुआ, अतरू उसके खिलाफ नकारात्मक टिप्पणी करना उचित नहीं है। जबकि जस्टिस श्रीधरन ने एनएचआरसी की कुल भूमिका पर सख्त आलोचनात्मक बातें कहीं। कहा कि जब मुसलमानों पर अत्याचार या उनकी लिंचिंग होती है, तो एनएचआरसी उन घटनाओं का संज्ञान नहीं लेता। उन्होंने ध्यान दिलाया कि एनएचआरसी का गठन मानव अधिकार अधिनियम 1993 के तहत हुआ था। उस कानून में मानव अधिकार की परिभाषा मौजूद है। उसके मुताबिक वे अधिकार इस दायरे में आएंगे, जिन्हें भारतीय संविधान में व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया है।

साथ ही जो अंतरराष्ट्रीय संधियां भारत में लागू हैं, उनमें वर्णित अधिकार भी मानव अधिकार के दायरे में आते हैं। न्यायमूर्ति श्रीधरन ने कहा कि ऐसे अधिकारों की रक्षा तक खुद को सीमित रखने के बजाय एनएचआरसी वैसे मामलों में दखल दे रहा है, जिन्हें सामान्यतरू संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जन हित याचिका के जरिए अदालतों के सामने लाया जाना चाहिए। आज के दौर में संवैधानिक या वैधानिक संस्थाओं की बनी भूमिका के संदर्भ में ये टिप्पणी बेहद अहम है। यह इस आम धारणा की पुष्टि करती है कि ये संस्थाएं अपेक्षित कार्य करने के बजाय किसी राजनीतिक परियोजना से संचालित हो रही हैं। अतरू जस्टिस शरण की आपत्ति तकनीकी रूप से जायज है, लेकिन जस्टिस श्रीधरन ने जो कहा, उसका संदर्भ व्यापक है।

राजनीति सनातन विरोध की बजाय आममुद्दों पर केंद्रित हो

ललित

भारतीय राजनीति के वर्तमान परिदृश्य में एक ऐसा विमर्श लगातार उभर रहा है, जिसने राजनीतिक बहस को विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मूल प्रश्नों से हटाकर धार्मिक पहचान और आस्था के इर्द–गिर्द खड़ा कर दिया है। यह विमर्श है–सनातन समर्थन बनाम सनातन विरोध। आज देश में एक ओर सनातन संस्कृति को भारतीय जीवन का शाश्वत आधार मानने वाली शक्तियां हैं, तो दूसरी ओर कुछ राजनीतिक वक्तव्य और प्रवृत्तियां ऐसी दिखती हैं जिन्हें जनमानस सनातन विरोध के रूप में देखता है। प्रश्न यह नहीं कि किसी विचारधारा से सहमति या असहमति क्यों है, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या राजनीति का केंद्र धर्म होना चाहिए या जनजीवन के वास्तविक मुद्दे? भारत का लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष संविधान पर आधारित है, जहां राज्य का कार्य किसी धर्म का पक्ष या विरोध नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। राजनीतिक दलों का दायित्व भी यही होना चाहिए कि वे जनता की समस्याओं, विकास और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दें। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक विमर्श राजनीति का बड़ा केंद्र बन गया है। सनातन केवल एक धार्मिक शब्द नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की सांस्कृतिक चेतना, जीवन–दर्शन और मूल्य परंपरा का प्रतीक है। "सत्यं वद, धर्मं चर", "वसुधैव कुटुम्बकम्", "सर्वे भवन्तु सुखिनः" जैसे सूत्र इसी सनातन दृष्टि के अंग हैं। इसलिए जब कोई राजनीतिक वक्तव्य सनातन को लेकर अपमानजनक या आक्रामक भाषा का उपयोग करता है, तो उसका प्रभाव केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक स्तर पर भी पड़ता है। तमिलनाडु में द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म की तुलना बीमारी से करने वाला वक्तव्य इसी कारण व्यापक विवाद का कारण बना। विपक्ष के अनेक दलों ने उससे दूरी बनाने का प्रयास किया, क्योंकि यह स्पष्ट था कि भारत जैसे देश में करोड़ों लोगों की आस्था को आहत करने वाला कथन राजनीतिक रूप से भी असहज स्थिति उत्पन्न करेगा। यहां यह समझना आवश्यक है कि द्रविड़ आंदोलन की अपनी ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि रही है। उसका मूल संघर्ष सामाजिक विषमताओं और जातीय वर्चस्व के विरुद्ध था। लेकिन जब सामाजिक सुधार का विमर्श पूरे धर्म या संस्कृति के विरोध जैसा प्रतीत होने लगे, तब वह जनस्वीकृति खो देता है। यह भी सत्य है कि अनेक विपक्षी दल स्वयं को सनातन विरोधी नहीं, बल्कि सामाजिक कुरीतियों, जातिवाद और भेदभाव के विरोधी बताते हैं। उनका तर्क है कि वे सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं। यह दृष्टि लोकतंत्र में स्वीकार्य है, क्योंकि हर परंपरा में आत्मसमीक्षा और सुधार की आवश्यकता होती है। स्वयं भारतीय दर्शन में भी संवाद, बहस और आत्मचिंतन की परंपरा रही है। बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, दयानंद और गांधी–सभी ने समाज की विसंगतियों पर प्रश्न उठाए, लेकिन उन्होंने समाज को तोड़ने नहीं, सुधारने का मार्ग चुना। समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीतिक भाषा संतुलन खो देती है। जब आलोचना सुधार की जगह अस्वीकार की भाषा बन जाती है, तब वह समाज में धुवीकरण को जन्म देती है। भारत जैसे बहुलतावादी देश में यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं कही जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का विमर्श अधिक प्रभावी होकर उभरा है। राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर,

महाकाल लोक, सांस्कृतिक धरोहरों के पुनरुत्थान जैसे विषयों ने एक बड़े वर्ग में सांस्कृतिक आत्मविश्वास को मजबूत किया है। इससे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ भी मिला। दूसरी ओर विपक्षी दल इस बदलते राजनीतिक मानस को समझने में कई बार असहज दिखाई दिए। कहीं उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और आस्था के बीच संतुलन बनाने में चूक की, तो कहीं उनके कुछ नेताओं के बयान उन्हें कठिन स्थिति में ले आए। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक चुनावी राजनीति में यह देखा गया कि केवल जातीय समीकरण या पारंपरिक वोट बैंक अब पर्याप्त नहीं हैं। जनता सांस्कृतिक पहचान, विकास और राष्ट्रीय विमर्श को भी महत्व देने लगी है। ऐसे में यदि कोई दल हिंदू आस्था के प्रति असंवेदनशील दिखता है, तो उसका राजनीतिक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन इस पूरे विमर्श का दूसरा पक्ष भी है। क्या राजनीति का उद्देश्य केवल धार्मिक पहचान के आधार पर समर्थन जुटाना होना चाहिए? क्या देश के सामने मौजूद बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि संकट, आर्थिक असमानता और सामाजिक विघटन जैसे प्रश्न पीछे छूट जाने चाहिए? यह चिंता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भारतीय राजनीति में पिछले कुछ वर्षों के दौरान धर्म, विशेषकर सनातन और हिंदू आस्था को लेकर कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, द्रमूक आदि विपक्षी दलों एवं उनके कुछ नेताओं द्वारा दिए गए बयानों को व्यापक जनसमुदाय ने सनातन पर आक्षेप या हिंदू भावनाओं के प्रति असंवेदनशीलता के रूप में देखा, जिसके राजनीतिक प्रभाव भी दिखाई दिए। किंतु इस विषय को केवल "हिंदू विरोध" बनाम "राजनीतिक विरोध" के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। भारत एक लोकतांत्रिक और बहुलतावादी राष्ट्र है, जहां किसी भी राजनीतिक दल को सरकार, नीतियों या नेतृत्व का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यदि वह विरोध आस्था, संस्कृति और बहुसंख्यक समाज की भावनाओं से टकराता हुआ प्रतीत हो, तो उसका राजनीतिक मूल्य चुकाना पड़ सकता है। यही कारण है कि कई दलों के लिए यह धारणा चुनौती बनी कि वे सत्ता–विरोध की राजनीति करते–करते सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनाओं से दूर हो गए हैं। भारत में सनातन केवल धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि जीवन–दर्शन, परंपरा, संस्कृति, सहिष्णुता और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उसके प्रति असावधान भाषा या नकारात्मक संकेत जनमानस में प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करते रहे हैं। दूसरी ओर लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा यह भी अपेक्षा करती है ।

आर्थिक संयम की अपील : राष्ट्रवाद या संकट प्रबंधन

अरुण

सबसे गंभीर प्रश्न संसदीय लोकतंत्र और संसद में जवाबदेही से जुड़ा है । इतने महत्वपूर्ण वैश्विक संकट पर संसद में व्यापक चर्चा और सर्वसम्मत नीति–निर्माण अपेक्षित था, लेकिन सरकार की सक्रिय पहल का अभाव दिखा। विपक्ष के सुझावों की अनदेखी और संवाद की कमी से संकट प्रबंधन संस्थागत विमर्श के बजाय सीमित दायरे में सिमटता प्रतीत होता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव से आपूर्ति शृंखलाएं और तेल कीमतें प्रभावित हैंय ऐसे में 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए विदेश यात्रा व सोने की खरीद टालने, पेट्रोल डीजल की खपत घटाने, सार्वजनिक परिवहन, कार पूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने तथा जीवनशैली में बदलाव का आह्वान किया। उन्होंने पार्सल ढुलाई को रेल से और वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने की भी सलाह दी।यह अपील सतही तौर पर श्आर्थिक राष्ट्रवादश लगती है, पर संदर्भ में यह वैश्विक अस्थिरता और घरेलू दबावों की आपात प्रतिक्रिया प्रतीत होती है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने भारत जैसे आयात–निर्भर देश पर दबाव बढ़ाया है। इसी पृष्ठभूमि में रुपया 95 प्रति डॉलर के पार पहुंचाकृजो बाह्य क्षेत्र पर बढ़ते दबाव का संकेत है, जहां हाल के महीनों में निर्यात–आयात असंतुलन से बढ़ता चालू खाता घाटा और उससे भी अधिक पूंजीगत खाते की कमजोरीकृविशेषकर विदेशी निवेश, बाहरी उधारी और अन्य पूंजी प्रवाह में कमीकृरुपये पर दबाव के प्रमुख कारण रहे हैं।ऊर्जा और सोने पर भारी आयात निर्भरता भारत की संरचनात्मक कमजोरी रही है। तेल और सोने की ऊंची कीमतें डॉलर की मांग बढ़ाती हैं। खाड़ी देशों से प्रेषण पर अनिश्चितता ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। इस दबाव के बीच तेल वितरण कंपनियों को लगभग रुपए 1000 करोड़ का घाटा प्रतिदिन हो रहा है और खरीफ सीजन से पहले उर्वरकों के कच्चे माल जैसे प्राकृतिक गैस, पोटाश, अमोनिया जैसे रसायनों का महंगा आयात भी अपरिहार्य है। रासायनिक उर्वरकों की कमी या महंगाई से कृषि उत्पादन प्रभावित होने और खाद्य कीमतों पर दबाव बढ़ने की आशंका है, जो समय रहते नियंत्रण न होने पर खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौती बन जायेगी। ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील मूलतरू डॉलर की मांग घटाने का एक श्आसान विकल्पश भर है, जबकि परिस्थितियां कीमतों के यथार्थपरक समायोजन जैसे कठिन, पर अधिक प्रभावी, निर्णयों की मांग करती हैं।व्यवहारिक स्तर पर भी इस अपील की सीमाएं स्पष्ट हैं। अधिकांश शहरों में सार्वजनिक परिवहन अव्यवस्थित, भीड़भाड़ वाला और समय–साध्य है। दूसरी ओर, राजनीतिक रैलियों, सरकारी काफिलों और आयोजनों में संसाधनों का व्यापक उपयोग श्कथनी और करनीश के अंतर को उजागर करता है। मध्यप्रदेश में निगम–मंडल अध्यक्षों का सैकड़ों वाहनों के साथ राजधानी भोपाल पदभार ग्रहण करने पहुंचना इस विरोधाभास को और गहरा करता है। यह विरोधाभास जनता से अपेक्षित संयम की नैतिक ताकत को कमजोर करता है।बाजार की प्रतिक्रिया ने इस अपील के निहितार्थ को और स्पष्ट किया। एविएशन, पर्यटन और ज्वेलरी क्षेत्रों में तेज गिरावट आई और एक ही दिन में लगभग 4 लाख करोड़ की बाजार पूंजीकरण में कमी दर्ज की गई। पेट्रोल कीमत में हालिया बढ़ोतरी ने निवेशकों की आशंका को पुष्ट कर दिया है, जबकि बढ़ते आर्थिक दबाव के कारण समग्र आर्थिक संतुलन बिगड़ने की संभावना भी बनी हुई है। राजनीतिक समाचार ब्रीफ सरकार ने 69 दिनों के कच्चे तेल, एलएनजी और 45 दिनों के एलपीजी भंडार का हवाला देकर स्थिति को नियंत्रित बताया है, लेकिन दीर्घकालिक संकट की स्थिति में यह पर्याप्त नहीं माना जा सकता। इससे ऊर्जा नीति की सीमाएं भी उजागर होती हैं। सौर, पवन और भंडारण जैसी वैकल्पिक ऊर्जा में निवेश की गति धीमी है और इलेक्ट्रिक वाहनों, इंडक्शन कुकिंग तथा बायोगैस जैसे विकल्पों का विस्तार सीमित है। पेट्रोलियम भंडारण क्षमता भी पिछले एक दशक से नहीं बढ़ी है। 2003 में शुरू हुई रणनीतिक भंडारण परियोजना का दूसरा चरणकृजिसे 2021 में मंजूरी मिलीकृबजट और प्रक्रियागत देरी के कारण अब तक जमीन पर नहीं उतर सका है, परिणामस्वरूप पेट्रोलियम पर निर्भरता कम नहीं हो पाई है। नोटबंदी और कोविड लॉकडाउन की तरह इस बार भी अपील के बाद स्थिति स्पष्ट करने के लिए मंत्रियों को सामने आना पड़ा, जो संकेत देता है कि निर्णय और उसके प्रभावों के आकलन के बीच संतुलन अक्सर कमजोर रहता है। भारत की विदेश नीति के क्रियान्वयन पर भी प्रश्न उठते हैं। संकट की इस संवेदनशील घड़ी में शीर्ष स्तर की पश्चिम एशिया यात्राओं का समय और प्राथमिकता स्पष्ट रणनीतिक संदेश नहीं दे पातीं। बढ़ते तनाव के बीच ऐसी सक्रियता कूटनीतिक पहल तो दिखाती है, पर उसके ठोस परिणामों और रणनीतिक लाभों पर पारदर्शिता का अभाव बना रहता है। सबसे गंभीर प्रश्न संसदीय लोकतंत्र और संसद में जवाबदेही से जुड़ा है । इतने महत्वपूर्ण वैश्विक संकट पर संसद में व्यापक चर्चा और सर्वसम्मत नीति–निर्माण अपेक्षित था, लेकिन सरकार की सक्रिय पहल का अभाव दिखा। विपक्ष के सुझावों की अनदेखी और संवाद की कमी से संकट प्रबंधन संस्थागत विमर्श के बजाय सीमित दायरे में सिमटता प्रतीत होता है। सांस्कृतिक पहल के नाम पर मंदिरों में स्वर्णमंडन की भव्य परियोजनाओं के बीच सोना न खरीदने की अपील एक विरोधाभास पैदा करती है। एक ओर आर्थिक संयम का संदेश है, तो दूसरी ओर स्वर्ण उपयोग का विस्तार श्स्वर्ण संसाधन अवरोधश को बढ़ावा देता दिखता है। भारतीय रिजर्व बैंक भी हाल के वर्षों में अपने स्वर्ण भंडार में लगातार वृद्धि कर रहा है। मार्च 2026 तक बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी बढ़कर 16.7प्रतिशत हो गई, जो छह महीने पहले 13.92प्रतिशत थी। वैश्विक स्तर पर कई केंद्रीय बैंक आर्थिक अनिश्चितता और बाजार अस्थिरता से बचाव के लिए सोना एक सुरक्षित संपत्ति के रूप में बढ़ा रहे हैं, जो संस्थागत स्तर पर इसके महत्व को दर्शाता है। हालांकि सोना खरीदना व्यक्तिगत रूप से गलत नहीं है, पर यह केवल निजी पसंद नहीं, बल्कि भारत की पारंपरिक बचत प्रवृत्ति और आधुनिक आर्थिक आवश्यकताओं के बीच एक संरचनात्मक द्वंद्व भी है। ऐसे में नीति–निर्माण के स्तर पर इन दोनों प्रवृत्तियों के बीच अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता महसूस होती है। भारत यात्रा गाइड यद्यपि भारत के पास लगभग 690 बिलियन डॉलर का पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकारों (एसडीआर) का आपात उपयोग भी नहीं करना पड़ा है, इसलिए 1990–91 जैसी गंभीर स्थिति की आशंका फिलहाल कम हैय तथापि विलंब से उठाए गए कदमों के बीच ऐसी अपील आर्थिक रूप से उचित प्रतीत होती है, पर इसकी प्रभावशीलता सरकार की नीतिगत सुसंगति और विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। यदि समय रहते ऊर्जा विविधीकरण, आयात निर्भरता में कमी और संस्थागत संवाद मजबूत किए गए होतेकृसाथ ही अस्थिर विदेशी संस्थागत व पोर्टफोलियो निवेश को आकर्षित करने वाली नीतियां सुधारी जातीं।

राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2029 में मुकाबला करेंगे

अजय दीक्षित

हाल ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा 2029 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी विपक्ष के गठबन्धन के नेता होंगे। हालांकि अभी से 2029 के लोकसभा चुनाव पर टिप्पणी करना बहुत जल्द बाजी होगी क्योंकि अभी दो वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन लगता है कि लोकसभा से अलग राज्यों के चुनावों को समय समय पर आए परिणामों से कुछ हद तक पड़ा जा सकता है। अभी लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली हरियाणा, असम उड़ीसा, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, केरल पांडिचेरी, त्रिपुरा , सिक्किम,तमिलनाडू, तेलंगाना,के चुनाव होगया और इस 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब गुजरात,गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,में होने है ।2028 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक,छत्तीसगढ़,के चुनाव होंगे , ओडिशा, आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ होंगे। नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,भी 28 में चुनाव संभावित है। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सरकार है जबकि तमिलनाडु में इंडिया ब्लॉक, तेलंगाना, कर्नाटक,केरल में कांग्रेस सरकार है। राजनीतिक दृष्टि से देखे तो हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल,में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पिछड़ने के बाद विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक चुनाव महत्व पूर्ण होगे। अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में वापिसी करती है तो 2029 फतह करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कांग्रेस के लिए 2029 का चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी लोकसभा में विपक्ष की 230 सीट है जिसमें कांग्रेस की 100 और तृणमूल कांग्रेस की 29 , सपा 38,डीएमके 37,एनसीपी,शिव सेना, नेशनल कॉन्फ्रेंस की 04 ,राजद, और बहुत दल शामिल हैं। टीवी रिपोर्टर और चुनाव विशेषज्ञ यशवंत देशमुख, मिलिंद खांडेकर, राजीव रंजन, आशुतोष, शाजिया इल्मी, जयंत घोषाल का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अब 240 से बहुत आगे निकल चुकी है ।उसे आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार,40 , महाराष्ट्र 48, उत्तर प्रदेश 80, पश्चिमी बंगाल 42, हरियाणा 10, की कुल 220 सीट में से 80 फीसदी सीट मिल सकती है। मप्र,29 राजस्थान 25, दिल्ली,07 छत्तीसगढ़,11 ओडिशा 20, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड 09 की कुल 91 सीट में से नब्बे फीसदी सीट मिल सकती है। असम 13, अरुणाचल प्रदेश 02, त्रिपुरा 04, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड की एक एक कुल मिलाकर 22 में कम से कम 18 लोकसभा सीट मिल सकती है। कुलमिलाकर अनुमान है कि 320 सीट बीजेपी जीत सकती है जबकि एनडीए 350 तक जा सकता है। दक्षिण भारत में तेलंगाना मिला कर 35 सीट मिल सकती है दक्षिण भारत में केरल 20, तमिलनाडु में 39, आंध्र प्रदेश 22 तेलंगाना 17, कर्नाटक में 28 कुलमिलाकर 126 सीट है यहां पर कांग्रेस को विजय की पार्टी के साथ 75 सीट मिल सकती है। विपक्ष का जो भी गठबन्धन बने नेता राहुल गांधी ही होंगे क्योंकि बंगाल से ममता बनर्जी की हार से राहुल गांधी के लिए विपक्ष के नेता बनने का रास्ता साफ हो गया है क्योंकि विजय,डीएमके के स्टालिन, राजेडी तेजस्वी यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, उनके नाम पर सहमत हो सकते हैं। केवल अरविंद केजरीवाल, सपा नेता अखिलेश स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि पंजाब में आप का मुकाबला कांग्रेस के साथ है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का मुकाबला बीजेपी से लेकिन कांग्रेस भी तम्मन्ना रखती है कि एक दर्जन सांसद हो उत्तर प्रदेश से । लेकिन अगर विधानसभा चुनाव में सपा कांग्रेस का समझौता नहीं हुआ तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से कुछ नहीं मिल सकता है।यह सही है कि राहुल गांधी के अलावा कोई विशेष नेता विपक्ष के पास नहीं है। हां अब ममता बनर्जी खाली है और उन्होंने कहा भी है कि अब वे इंडी एलायंस का हिस्सा है लेकिन राहुल गांधी उनको अब भाव नहीं देंगे क्योंकि जब वे बंगाल में सत्ता में थी तब राहुल गांधी को भाव नहीं देती थीं।उनकी बजह से ही नीतीश कुमार एनडीए में बापिस हुए।क्योंकि उन्होंने नीतीश को इंडी एलायंस का कन्वीनर मानने से इनकार कर दिया था। ममता बनर्जी को कोई भाव नहीं दे रहा है केवल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव रस्सी का सांप बनाना चाहते हैं। सीपीई, सीपीएम,लेफ्ट पार्टियों का कोई बाजूद नहीं रहा है।

नवा रायपुर अटल नगर– विकास, निवेश और आधुनिक भारत का उभरता स्मार्ट शहर

सुनील कुमार त्रिपाठी

छत्तीसगढ़ की आधुनिक और योजनाबद्ध राजधानी नवा रायपुर अटल नगर आज देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे स्मार्ट शहरों में शामिल है। सुव्यवस्थित अधोसंरचना, हरित विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी, पर्यटन और महिला सशक्तिकरण जैसे विविध क्षेत्रों में हुई उल्लेखनीय प्रगति ने नवा रायपुर को भविष्य के भारत का आदर्श शहरी मॉडल बना दिया है। यह केवल प्रशासनिक राजधानी नहीं, बल्कि निवेश, नवाचार और समावेशी विकास का उभरता हुआ केंद्र है। स्मार्ट अधोसंरचना और शहरी सेवाओं में बड़ी उपलब्धियाँ नवा रायपुर अटल नगर में 52 एमएलडी क्षमता की पाइपलाइन और अत्याधुनिक जल शोधन संयंत्र के माध्यम से पूरे शहर में दीर्घकालिक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इससे वर्तमान आबादी के साथ–साथ नए विकसित हो रहे सेक्टरों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो सकेगी। वर्षाजल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देने के लिए 10.66 किलोमीटर लंबी बायोस्वेल्स, रिचार्ज पिट्स और प्राकृतिक जल निकासी तंत्र विकसित किए गए हैं। इन पहलों ने न केवल जल संरक्षण को मजबूत किया है, बल्कि शहर के पर्यावरणीय संतुलन को भी सुदृढ़ किया है। परिवहन और कनेक्टिविटी को मिला नया आयाम रायपुर–राजिम रेल सेवा का नवा रायपुर के सीबीडी स्टेशन तक विस्तार शहर की कनेक्टिविटी को नई गति प्रदान कर रहा है। महिलाओं की सुरक्षित आवाजाही और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पिंक ई–रिक्शा सेवा शुरू की गई है। साथ ही, ई–बस संचालन के लिए आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है और सेवा प्रारंभ होने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यह पहल हरित और टिकाऊ शहरी परिवहन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा के क्षेत्र में विकसित हो रहा एडूसिटी नवा रायपुर के 13 सहकारी विद्यालयों का उन्नयन किया गया है और दो उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किया गया है। लगभग 200 एकड़ क्षेत्र में एडूसिटी का विकास किया जा रहा है, जहाँ राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, नरसी मोंजी को भूमि आवंटित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सेक्टर–7 में 17 एकड़ भूमि पर आवासीय विद्यालय की स्थापना प्रस्तावित है। मेडिसिटीरू स्वास्थ्य सेवाओं का नया केंद्र मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग 500 एकड़ क्षेत्र में विश्वस्तरीय मेडिसिटी विकसित की जा रही है। यहाँ सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, डायग्नोस्टिक सेंटर, धर्मशाला, होटल और आवासीय सुविधाएँ विकसित की जाएँगी। इस परियोजना के तहत बॉम्बे अस्पताल को 300 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए भूमि आवंटित की जा चुकी है। साथ ही, लगभग 50 एकड़ भूमि पर आवासीय विकास हेतु निजी निवेशकों को भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें लगभग 350 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना है। महिला सशक्तिकरण और श्रमिक कल्याण कार्यरत महिलाओं के लिए 1,000 क्षमता वाले वर्किंग वुमन हॉस्टल का निर्माण 109 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। यह परियोजना महिला सुरक्षा, सुविधा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी। इसके अतिरिक्त, प्रवासी श्रमिकों के लिए 1,100 क्षमता वाला सर्वसुविधायुक्त श्रमिक आवास भवन 40 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है। पर्यटन, संस्कृति और एमआईसीई गंतव्य के रूप में उभार नवा रायपुर में 77 एकड़ भूमि पर सेवाग्राम तथा सेक्टर–39 में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को 40 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जहाँ सांस्कृतिक और सामुदायिक गतिविधियों के बड़े केंद्र विकसित हो रहे हैं। सेक्टर–4 और 10 में लगभग 120 एकड़ क्षेत्र में निजी निवेश के माध्यम से कन्वेंशन सेंटर कम स्पोर्ट्स सिटी विकसित की जा रही है। लगभग 800 करोड़ रुपये की इस परियोजना में विश्वस्तरीय कन्वेंशन सेंटर और टेनिस, तैराकी, कुश्ती, तीरंदाजी तथा स्क्वैश जैसी खेल सुविधाएँ शामिल होंगी। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का उभरता हब नवा रायपुर में राज्य का पहला एसईजेड आधारित एआई डेटा सेंटर पार्क स्थापित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 4,000 करोड़ रुपये का निजी निवेश अपेक्षित है। यहाँ भारत का पहला जीएएन तकनीक आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने के लिए भी भूमि आवंटित की गई है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हुई है, जहाँ पीसीबी प्रोटोटाइपिंग, 3डी प्रिंटिंग और ईएमसी टेस्टिंग जैसी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। सीबीडी क्षेत्र में प्लग–एंड–प्ले मॉडल पर आईटी कंपनियों को सुसज्जित कार्यालय स्थान उपलब्ध कराए गए हैं। वर्तमान में लगभग 1,000 युवा कार्यरत हैं और 2,000 अतिरिक्त रोजगार सृजन की संभावना है। सतत विकास और हरित पहल ष्पीपल फॉर पीपलष अभियान के अंतर्गत 1 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं, जिससे शहर के 26 प्रतिशत हरित क्षेत्र को संरक्षित और विस्तारित करने में मदद मिली है। बायोस्वेल्स, रिचार्ज सिस्टम और हरित कॉरिडोर जैसे उपाय नवा रायपुर को पर्यावरण–अनुकूल और जल–संवेदनशील शहर के रूप में स्थापित कर रहे हैं। प्राधिकरण की आगामी कार्ययोजना नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण आने वाले वर्षों में शहर को और अधिक आधुनिक एवं निवेश–आकर्षक बनाने हेतु कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। सेरीखेड़ी और मंदिरहसौद क्षेत्र में लगभग 1,100 एकड़ पर 800 करोड़ रुपये की लागत से अधोसंरचना विकास। राज्य राजधानी क्षेत्र के एकीकृत विकास हेतु विशेष प्राधिकरण गठन। 500 एकड़ में मेडिसिटी और 200 एकड़ में एडूसिटी का विस्तार। नवा रायपुर को आईटी, आईटीईएस और एआई हब के रूप में स्थापित करना। वार्षिक पूंजीगत व्यय क्षमता को 1,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाना। वेलनेस सेंटर, वेडिंग डेस्टिनेशन, एमआईसीई कैपिटल और पर्यटन परियोजनाओं में निजी निवेश को प्रोत्साहन। प्रभावित ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास योजना के आधार पर आधुनिक अधोसंरचना विकास। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का तकनीकी उन्नयन। सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने हेतु 40 नई ई–बसों का संचालन। नई राजधानी, नए भारत की पहचान नवा रायपुर अटल नगर आज योजनाबद्ध विकास, आधुनिक सुविधाओं और सतत शहरीकरण का सशक्त उदाहरण बन चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और हरित विकास के क्षेत्रों में निरंतर प्रगति इसे न केवल छत्तीसगढ़ की नई पहचान बना रही है, बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरक मॉडल के रूप में स्थापित कर रही है। आने वाले वर्षों में नवा रायपुर अटल नगर निश्चित ही भारत के सबसे आधुनिक, निवेश–अनुकूल और जीवन गुणवत्ता से परिपूर्ण शहरों में अग्रणी स्थान प्राप्त करेगा।

बदली जाएगी प्रदेश की विधानसभा, सहारा शहर की जमीन पर विधानभवन बनना तय

लखनऊ, (संवाददाता)। गोमतीनगर स्थित सहारा शहर की जमीन पर विधानभवन बनना तय हो गया है। अब अधिकृत तौर पर इसके निर्माण की सूचना बाहर आ गई है। एलडीए ने डिजाइन और प्लॉनिंग के लिए कंसल्टेंट चयन की खातिर शुक्रवार को टेंडर (आरएफपी) भी जारी कर दिया है। विधानभवन कितने समय में बनकर तैयार होगा और कितना बजट खर्च होगा, यह डीपीआर बनने पर पता चलेगा। जिस जमीन पर विधानभवन बनेगा, वह 245 एकड़ है। इसमें 75 एकड़ जमीन ग्रीन बेल्ट के लिए एलडीए ने और 170 एकड़ जमीन नगर निगम ने सहारा शहर को आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए लीज पर दी थी। एलडीए ने करीब डेढ़ साल पहले, जबकि सितंबर में नगर निगम ने लीज के शर्तों के उल्लंघन पर जमीन दोबारा अपने कब्जे में ले ली थी। तब से इस जमीन पर विधानभवन बनाने की चर्चाएं हो रही हैं। शासन के निर्देश पर करीब छह महीने पहले जमीन की पैमाइश भी हुई थी। अब उच्च स्तर पर इस जमीन पर विधानभवन बनाने का निर्णय होने के बाद एलडीए ने कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। इसके लिए 23 मई से 21 जून तक टेंडर डाले जा सकेंगे। जानकारों का कहना है कि सरकार को नई विधानसभा बनाने के लिए करीब 200 एकड़ जमीन की तलाश थी। सहारा शहर से कब्जे में ली गई यह जमीन जगह, लोकेशन और आवागमन के हिसाब से सबसे उपयुक्त है। विधानसभा के साथ ही यहां सचिवालय, मुख्यमंत्री निवास व अन्य सरकारी कार्यालय भी बनाए जाएंगे। इसके चलते ही टेंडर में विधानभवन कॉम्प्लेक्स निर्माण की बात कही गई है।

भीषण गर्मी में बिजली कटौती का कहर, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सरकार पर दबाव बढ़ाया

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश में बढ़ती बिजली कटौती और खराब आपूर्ति व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सरकार पर दबाव बढ़ाया है। भाजपा विधायकों से लेकर कांग्रेस नेताओं तक ने मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर जनता की परेशानियों का मुद्दा उठाया है। नेताओं का कहना है कि भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली बाधित होने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है और जनता में भारी आक्रोश है। लखनऊ उत्तर से भाजपा विधायक नीरज बोरा ने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा को पत्र भेजकर कहा कि लगातार हो रही बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। उन्होंने मांग की कि आपूर्ति व्यवस्था में तत्काल सुधार किया जाए। साथ ही अपने कैंप कार्यालय में मुख्य अभियंता को भेजने की मांग भी की, ताकि वहां पहुंचने वाली जनता को

वास्तविक स्थिति की जानकारी दी जा सके। वहीं, सरोजनीनगर से भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने भी ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि बार–बार बिजली बाधित होना, लो वोल्टेज, ट्रांसफार्मरों का ओवरलोड होना, फीडर ट्रिपिंग और अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट जैसी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समस्या हर साल सामने आती है, इसलिए इसका स्थायी समाधान निकालने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए। विधायक ओपी श्रीवास्तव ने भी ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने लखनऊ पूर्व विधानसभा क्षेत्र में खराब बिजली व्यवस्था पर चिंता जताई। विधायक ने जर्जर लाइनों और ट्रांसफार्मरों की तत्काल मरम्मत की मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी बिजली संकट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोग बिजली कटौती से बेहाल हैं। लोगों को रातभर जागना पड़ रहा है। बिजली न होने से पेयजल संकट गहरा गया है, पंपसेट बंद पड़े हैं और बिजली आधारित लघु उद्योग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आपूर्ति व्यवस्था में सुधार की मांग की तथा चेतावनी दी कि हालात नहीं सुधरे तो कांग्रेस सड़क पर आंदोलन करेगी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने अत्यधिक गर्मी से मांग बढ़ने की बात कही है। उन्होंने दावा किया कि विभाग व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि कराई जा रही है और निर्धारित रोस्टर के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित है। उन्होंने आजमगढ़ के सठियांव में बिजली कैंप का दौरा कर आम जनता से संवाद भी किया। पावर कार्पोरेशन के निदेशक (वितरण) ज्ञानेंद्रधर द्विवेदी ने बयान जारी किया है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था सुचारु बनी हुई है। अधिकारियों को बाधित बिजली की अतिरिक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश हैं। खराब ट्रांसफार्मर को कम समय में बदलने का प्रयास किया जा रहा है।

संक्षिप्त खबरें

लखनऊ की महापौर और हाईकोर्ट के बीच टकराव की नौबत

लखनऊ, (संवाददाता)। कोर्ट से निर्वाचित घोषित किए गए पार्षद ललित तिवारी को शपथ न दिलाने पर बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट ने महापौर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज कर दिए। इसके बाद भी शुक्रवार देर शाम तक महापौर की ओर से शपथ ग्रहण के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। ऐसे में ललित की शपथ पर अभी भी संशय बना हुआ है। चर्चा है कि इस मामले में महापौर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शपथ ग्रहण कब होगा, इस बाबत जब महापौर सुषमा खर्कवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह अभी अस्पताल में भर्ती हैं। जब वापस लौटेंगी तब इस बारे में बताएंगी। हालांकि, हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जब तक ललित का शपथ ग्रहण नहीं होगा महापौर के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज रहेंगे। इस दौरान उनको शपथ दिलाने का अधिकार रहेगा। इस प्रकरण में याचिकाकर्ता ललित किशोर तिवारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी ओर से क्या कहूं। कोर्ट ने खुद ही अपने आदेश में सब कुछ कह दिया है। आदेश का अनुपालन महापौर को कराना है। इस प्रकरण पर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा कि शपथ दिलाने का अधिकार महापौर को है। इस बारे में वही निर्णय लेंगी। 22 जुलाई को होगी प्रदीप की अपील पर सुनवाई इस मामले में प्रभावित फैजुल्लागंज तृतीय वार्ड के भाजपा पार्षद प्रदीप शुक्ला टिंकू का कहना है कि अपर जिला जज की कोर्ट से उनका निर्वाचन शून्य घोषित कर ललित तिवारी को पार्षद निर्वाचित किए जाने के आदेश के विरोध में उन्होंने हाईकोर्ट में प्रथम अपील कर रखी है। उस पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ। अपील पर सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख लगी है। कोर्ट के निर्णय आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी।

संवेदनशील 31 उपकेंद्रों पर तैनाती होगी पीएसी

लखनऊ, (संवाददाता)। राजधानी के 31 संवेदनशील विद्युत उपकेंद्रों पर पीएसी तैनात होगी जो कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ ही उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई करेगी। यह निर्देश जिलाधिकारी विशाख जी ने शुक्रवार राजधानी की बिजली व्यवस्था की समीक्षा के दौरान दिए। जिलाधिकारी को बताया गया कि कुछ अराजक तत्व नियोजित तरीके से 31 बिजलीघरों का रात में घेराव करने के साथ बंद बिजली को चालू करने में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। इनमें लौलाई, शिवपुरी चिनहट, उतरेटिया, अंबेडकर उपकेंद्र, एफसीआई, बनी, गहरू, सरोसा–भरोसा, राजाजीपुरम ओल्ड व न्यू, आरडीएसओ, दुबग्गा, इंजीनियरिंग कॉलेज, न्यू कैम्पस, जीपीआरए, अहिबरनपुर, विकासनगर, अपट्रॉन, नूरबाड़ी न्यू व ओल्ड, विक्टोरिया, राधा ग्राम, चौपटिया, हुसैनगंज, पुरनिया, जीएसआई आदि हैं। उन्होंने मध्यांचल निगम मुख्यालय में तैनात निदेशकों, मुख्य अभियंताओं को संवेदनशील बिजलीघरों की रात में निगरानी करने के निर्देश भी दिए।

तालाब में डूबने से किशोरी की मौत, बचाने उतरी दो महिलाएं भी डूबीं

लखनऊ, (संवाददाता)। अंबेडकरनगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के दहीरपुर गांव में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। मवेशी चराने गई 13

वर्षीय किशोरी की तालाब में डूबने से मौत हो गई। उसे बचाने के लिए तालाब में उतरी दो महिलाएं भी डूबने लगीं, जिन्हें आसपास के लोगों ने किसी तरह बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार सैदपुर गांव निवासी जितेंद्र की 13 वर्षीय बेटी रूही शनिवार सुबह गांव की सुनहरा देवी और विताबाद देवी के साथ डीएम आवास के सामने स्थित तालाब के पास मवेशी चरा रही थी। इसी दौरान रूही तालाब में नहाने के लिए उतर गई और गहरे पानी में चली गई। उसे डूबता देख साथ मौजूद दोनों महिलाएं बचाने के लिए तालाब में कूद पड़ीं, लेकिन वह भी पानी में डूबने लगीं। महिलाओं की चीख–पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद दोनों महिलाओं को बाहर निकाला। वहीं किशोरी को भी बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंच गए। घायल महिलाओं को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मर्चरी में रखवाया गया है। घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है।

बाराबंकी में दर्दनाक हादसा, घर के बाहर सो रहे परिवार पर चढ़ा डंपर

लखनऊ, (संवाददाता)। बाराबंकी जिले के फतेहपुर–भनौली मार्ग पर शनिवार सुबह एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। ग्राम झांसा के पास सड़क किनारे मच्छरदानी लगाकर सो रहे एक परिवार को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया। हादसे में पिता, दो बेटे और एक बेटी की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मां जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। इस हृदयविदारक घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम झांसा निवासी नीरज चौहान (36) अपनी पत्नी आरती चौहान (34), पुत्र अनुराग (12), आशू (8) तथा पुत्री आंशिक (10) के साथ सड़क किनारे जमीन पर मच्छरदानी लगाकर सो रहे थे। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी के कारण परिवार घर के बाहर सोने को मजबूर था। इसी दौरान सुबह करीब तीन बजे महमूदाबाद की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे एक डंपर ने अनियंत्रित होकर पूरे परिवार को रौंद दिया। हादसा

इतना भयावह था कि नीरज चौहान और बड़े पुत्र अनुराग की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चीख–पुकार मच गई। आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल आरती, आशिका और आशू को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद तीनों की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में मासूम अंशिका व आशू ने भी दम तोड़ दिया। एक ही परिवार के चार लोगों की मौत से गांव में कोहराम मचा हुआ है।

संक्षिप्त खबरें

नीट पेपर लीक, महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में सपा युवा प्रकोष्ठों का प्रदर्शन

लखनऊ, (संवाददाता)। समाजवादी पार्टी के युवा प्रकोष्ठों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को नीट पेपर लीक, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी तथा डीजल–पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पेपर लीक की घटनाओं और बढ़ती कीमतों को लेकर विरोध जताया।समाजवादी पार्टी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश और देश में लगातार बढ़ती महंगाई तथा युवाओं के भविष्य से जुड़े प्रश्नों पर सरकार गंभीर नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक प्रकरण को लेकर भी सरकार को घेरते हुए युवाओं के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया।प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शन रोकने के दौरान अभद्र व्यवहार किया और कई कार्यकर्ताओं को सड़क पर घसीटते हुए हिरासत में लिया, जिससे कुछ युवाओं को चोटें भी आईं। वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर बसों के माध्यम से इको गार्डेन भेज दिया। प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के विभिन्न युवा संगठनों से जुड़े कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। इनमें राम प्रकाश मौर्य, राज साहनी, अजीत कुमार, विकास कुमार, जर्नादन यादव, शिवकेश, केशव प्रजापति, देवेश लोधी, मोनू यादव, गणेश शंकर, पंकज कुशवाहा, विकास यादव विशु, मुलायम सिंह यादव, संवरिया शिवम यादव और रवि प्रकाश सहित बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कालाबाजारी, घटतौली और राशन घोटाले पर सख्त हुए मंत्री मनोज पांडेय

लखनऊ, (संवाददाता)। खाद्य एवं रसद विभाग तथा नागरिक आपूर्ति व्यवस्था को लेकर कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि प्रदेश में कालाबाजारी, घटतौली, जमाखोरी, अवैध वसूली और गरीबों के अधिकारों में बाधा डालने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गरीबों के राशन में गड़बड़ी करने वाले, तौल में चोरी करने वाले और सरकारी व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर दोषियों को जेल भेजने की कार्रवाई भी की जाएगी, ताकि गरीबों और पात्र लाभार्थियों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि खाद्य एवं रसद विभाग से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी भी अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से समझें। यदि किसी स्तर पर लापरवाही, भ्रष्टाचार, शिकायतों की अनदेखी अथवा दोषियों को संरक्षण देने की बात सामने आती है, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोषी पाए जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा।कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता को पारदर्शी, ईमानदार और जवाबदेह व्यवस्था उपलब्ध कराना है।

गर्मी में ट्रेन का सफर मुश्किल, अधिक लोड होने से एसी कूलिंग ठप

लखनऊ, (संवाददाता)। भीषण गर्मी में ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्रियों का सफर मुहाल हो गया है। तपती बोगियों से यात्रियों के पसीने छूट रहे हैं। आरक्षित बोगियों में एसी कूलिंग ठप होने की शिकायतें नहीं थम रही हैं। हद यह है कि शिकायतों के बाद भी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा है। ताजा मामला ट्रेन संख्या 14009 चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस का है। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से लगभग सात घंटे की देरी से चली जिससे पूरे रास्ते यात्री परेशान होते रहे। भीषण गर्मी और उमस के बीच घंटों तक स्टेशनों पर ट्रेन का इंतजार करते रहे। ट्रेनों की लेटलतीफी यात्रियों के स्वास्थ्य पर भी असर डाल रही है। रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर निशुल्क ठंडे पानी और बैठने की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बुजुर्गों, महिलाओं और छोटे बच्चों को सर्वाधिक दिक्कत हो रही है। परेशान यात्रियों और उनके परिजनों ने सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से रेल प्रशासन से गुहार लगाई है कि चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस अन्य ट्रेनों का संचालन सामान्य किया जाए। 05634 स्पेशल ट्रेन छह घंटे देरी की शिकार हुई। यह ट्रेन गोरखपुर से ही देरी से रवाना हुई जिससे पूरे रूट पर यात्री परेशान होते रहे। 15621 कामाख्या आनंदविहार एक्सप्रेस भी सात घंटे देरी की शिकार हुई। 15017 काशी एक्सप्रेस में सफाई नहीं होने से यात्रियों को असुविधाएं हुईं। ऐसे ही 01080 गोरखपुर मुंबई स्पेशल की थर्ड एसी बोगी में सफर करने वाले मुसाफिरों ने एसी कूलिंग ठप होने की शिकायत की। यात्रियों का कहना था कि पूरे रूट एसी ने काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के करीब दो तिहाई जिले तेज धूप, गर्म पुरवा हवाओं और उमस भरी गर्मी की चपेट में हैं। दिन के साथ रातें भी तपिश से बेहाल कर रही हैं। शुक्रवार को बांदा, प्रयागराज, झांसी और आगरा समेत छह जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया।

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक सेवा वाहनों के लिए निगरानी यंत्र नियमों में बड़ा बदलाव

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक सेवा वाहनों में यात्रा को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और निगरानी आधारित बनाने के उद्देश्य से वाहन स्थिति निगरानी यंत्र (वीएलटीडी) को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। शासन ने एक जनवरी 2019 से पहले और बाद में पंजीकृत सभी सार्वजनिक सेवा वाहनों के लिए नए निर्माताओं के पंजीकरण, पुराने मॉडलों में संशोधन तथा कुछ कंपनियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव को मंजूरी दी है, ताकि वाहन स्वामियों और परिवहन कारोबारियों को यंत्र लगाने की प्रक्रिया अधिक सरल और सुलभ हो सके।यह जानकारी परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक सेवा वाहनों में वाहन स्थिति निगरानी यंत्र लगाने और उसे सक्रिय करने को लेकर शासन ने व्यापक निर्णय लिए हैं। नए निर्माताओं और मॉडलों को अनुमति देने के साथ पहले से स्वीकृत कंपनियों के वाहनों एवं मॉडलों में विस्तार, संशोधन और कुछ मामलों में विलोपन का अनुमोदन भी किया गया है।मंत्री ने बताया कि नई स्वीकृत कंपनियों में पीएसडीएन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को स्टेलेंटिस कंपनी के वाहनों में अपने यंत्र लगाने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार एक्यूट कम्युनिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एपीएम समूह प्राइवेट लिमिटेड तथा एपीएम किंग्सट्रैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी के वाहनों में निगरानी यंत्र लगाने की मंजूरी प्रदान की गई है।इसके अतिरिक्त यूनो मिंडा लिमिटेड की स्वीकृत यंत्र प्रणाली को टोयोटा कंपनी के अधिक मांग वाले मॉडलों इन्नोवा क्रिस्टा और इन्नोवा हायक्रॉस में लगाने की अनुमति दी गई है। पहले यह अनुमति अर्बन क्रूजर हाईराइडर और रूमियन मॉडल के लिए थी।परिवहन विभाग ने वाहन स्वामियों को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने के लिए पहले से स्वीकृत कंपनियों के दायरे का भी विस्तार किया है। रोजमर्टा ऑटोटेक लिमिटेड को पहले महिंद्रा और रेनो वाहनों तक सीमित अनुमति थी।

जैव विविधता संरक्षण के बिना मानव अस्तित्व पर संकट

लखनऊ, (संवाददाता)। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान स्थित सारस प्रेक्षागृह में आयोजित संगोष्ठी में वन, पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि जैव विविधता केवल एक अमूर्त अवधारणा नहीं, बल्कि मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं का आधार है। उन्होंने कहा कि अन्न, फल, औषधि, रेशे, पशु उत्पाद और पर्यटन सहित अनेक क्षेत्रों की निर्भरता जैव विविधता पर है तथा इसके संरक्षण के बिना मानव जीवन और अस्तित्व दोनों संकट में पड़ सकते हैं।वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना" विषयक संगोष्ठी का शुभारंभ करते हुए मंत्री ने कहा कि भारत का क्षेत्रफल विश्व का मात्र 2.5 प्रतिशत है, जबकि यहां विश्व की लगभग 16 प्रतिशत आबादी निवास करती है। इसके बावजूद भारत वैश्विक प्रजातियों में लगभग 7.5 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है, जो देश की समृद्ध परंपरा, संस्कृति और संरक्षण आधारित प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्राकृतिक जैव विविधता को सुरक्षित रखते हुए विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।कार्यक्रम के दौरान अरुण कुमार सक्सेना एवं अन्य अतिथियों ने उत्तर प्रदेश की जैव विविधता प्रतीक पोस्टर का अनावरण किया तथा अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया।प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड की अध्यक्ष वी. हेकाली झिमोमी ने जैव विविधता संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान वृद्धि और वातावरण में कार्बन की बढ़ती मात्रा पूरी दुनिया के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में जैव विविधता का क्षरण एक बड़ी बाधा बन रहा है। ऐसे में स्थानीय समुदायों को जैव विविधता के महत्व से जोड़ना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

प्रशिक्षण संस्थानों में बेहतर सुविधाएं हों सुनिश्चित : कपिल देव अग्रवाल

लखनऊ, (आरएनएस)। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने शुक्रवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पाण्डुनगर, कानपुर नगर का निरीक्षण कर प्रशिक्षण व्यवस्थाओं, संसाधनों और निर्माण कार्यों की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को संस्थान में पाई गई समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने तथा प्रशिक्षार्थियों को बेहतर प्रशिक्षण वातावरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने संस्थान में संचालित विभिन्न व्यवसायों एवं प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का विस्तृत अवलोकन किया। उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उनके कौशल विकास, प्रशिक्षण अनुभव और भविष्य की रोजगार संभावनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। मंत्री ने प्रशिक्षार्थियों को तकनीकी शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने और उद्योगों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने के लिए प्रेरित किया।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगारपरक और व्यवहारिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास संस्थानों का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि युवाओं को रोजगार योग्य बनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाना है। ऐसे में प्रशिक्षण संस्थानों को और अधिक प्रभावी तथा परिणामोन्मुख ढंग से कार्य करने की आवश्यकता है।

गर्मी में ट्रेनें लेट, यात्री बेहाल, एसी कूलिंग ठप

लखनऊ, (संवाददाता)। भीषण गर्मी में ट्रेनों की लेटलतीफी से यात्रियों का सफर मुहाल हो गया है। तपती बोगियों से यात्रियों के पसीने छूट रहे हैं। आरक्षित बोगियों में एसी कूलिंग ठप होने की शिकायतें नहीं थम रही हैं। हद यह है कि शिकायतों के बाद भी समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा है। ताजा मामला ट्रेन संख्या 14009 चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस का है। यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से लगभग सात घंटे की देरी से चली जिससे पूरे रास्ते यात्री परेशान होते रहे। भीषण गर्मी और उमस के बीच घंटों तक स्टेशनों पर ट्रेन का इंतजार करते रहे। ट्रेनों की लेटलतीफी यात्रियों के स्वास्थ्य पर भी असर डाल रही है। रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर निशुल्क ठंडे पानी और बैठने की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बुजुर्गों, महिलाओं और छोटे बच्चों को सर्वाधिक दिक्कत हो रही है। परेशान यात्रियों और उनके परिजनों ने सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से रेल प्रशासन से गुहार लगाई है कि चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस अन्य ट्रेनों का संचालन सामान्य किया जाए। 05634 स्पेशल ट्रेन छह घंटे देरी की शिकार हुई। यह ट्रेन गोरखपुर से ही देरी से रवाना हुई जिससे पूरे रूट पर यात्री परेशान होते रहे। 15621 कामाख्या आनंदविहार एक्सप्रेस भी सात घंटे देरी की शिकार हुई। 15017 काशी एक्सप्रेस में सफाई नहीं होने से यात्रियों को असुविधाएं हुईं। ऐसे ही 01080 गोरखपुर मुंबई स्पेशल की थर्ड एसी बोगी में सफर करने वाले मुसाफिरों ने एसी कूलिंग ठप होने की शिकायत की। यात्रियों का कहना था कि पूरे रूट एसी ने काम नहीं किया।

महापौर ने फतेहगंज से गुदड़ी बाजार चौराहा तक निकाली पदयात्रा

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।सोमवार को महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने पदयात्रा निकालकर लोगों का आह्वान किया कि आगामी 31 मई को सुबह 7रू00 बजे घर से निकलें और महज आध ा घंटा सफाई कर सामूहिक स्वच्छता का इतिहास रच दें। वह फतेहगंज चौराहा से अकब बजाजा, चौक होते हुए गुदड़ी बाजार चौराहे तक निकली पदयात्रा के दौरान लोगों से संपर्क कर रहे थे।इस दौरान जगह–जगह स्टिकर लगाकर आमजन को आगामी 31 मई को सुबह सात बजे नगर निगम क्षेत्र में चलाए जाने वाले स्वच्छता के महाअभियान श्एक रविवार, हर परिवार, करे गंदगी पर वारश में सहभागिता का संदेश दिया गया।पदयात्रा के दौरान महापौर ने लोगों के घरों पर दस्तक दी और सफाई के मामले में नगर को देश के टॉप टेन महानगरों में लाने में जन–जन से भागीदारी सुनिश्चित करने की अपेक्षा की।

पदयात्रा में शामिल नगर आयुक्त श्री जयेंद्र कुमार ने लोगों से कहा कि 31 मई को अपने घरों के आसपास महज आधा घंटा सफाई करने से नगर को साफ–सुथरा बनाने की प्रेरणा भी मिलेगी। नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश पांडेय ने बताया कि एक घंटे चली पदयात्रा में ध्वनि विस्तारक वाहनों से सूचना भी प्रसारित की और अभियान में शामिल होने के लिए फॉर्म भरने की भी जानकारी दी गई।इस यात्रा में अपर नगर आयुक्त डॉ. नागेंद्र नाथ, भारत भार्गव के अलावा वरिष्ठ पार्षद अनिल सिंह, हरिश्चंद्र अग्रहरि, दीप कुमार, अनीता द्विवेदी, पूर्व सभापति राजेश गौड़, अजय पांडेय, ज्ञान केसरवानी, सामाजिक कार्यकर्ता विजय सिंह बंटी, भाजपा के मंडल अध्यक्ष रवि सोनकर, हेमंत जायसवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष आलोक द्विवेदी, अमरेंद्र सिंह कर्फ्यू, नीलकमल अग्रवाल, सुबोध चतुर्वेदी, सतीश पांडे, प्रेमप्रकाश मिश्र, दीपांशु साहू, संजय साहू, पुर्णेन्द त्रिपाठी, आशीष कौर, रीना सिंह, रुचिरा सिंह, आलोक सिंह राना, श्रीनिवास शास्त्री आदि शामिल थे।

मूलभूत समस्याएं बनी राम नगरी की प्रमुख पहचान

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। पेयजल ,पार्किंग,जाम,सीवर लाइन के नाम पर सड़कों पर खुदे गड्ढे,गंदगी सहित कई समस्याएं रामनगरी की प्रमुख पहचान बन चुकी हैं। जिसके चलते यहां के स्थानीय लोगों के अलावा दूसरे प्रदेशों तथा देश–विदेश से राम मंदिर सहित अन्य प्रमुख मंदिरों पर दर्शन पूजन करने आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाए तो इस समय राम मंदिर निर्माण की वेस्ट श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रामनगरी आ रही है जिसके चलते चार पहिया के वाहनों में बढ़ोतरी तो संभव ही है। वाहनों को खड़ा करने के लिए चाहे ट्रैफिक विभाग हो या फिर नगर निगम पर्याप्त संख्या में पार्किंग का भाव है जिसका पूरा–पूरा लाभ अवैध रूप से अयोध्या धाम में कुछ लोग उठा रहे हैं यह सभी बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को खड़े करने के नाम पर मुंह मांगा पैसे भी वसूल रहे हैं। इसके अलावा बीच–बीच में यातायात पुलिस अन्य संबंधित विभागों के साथ लोगो को जाम से राहत देने के लिए बैठक तो कल ली जाती है लेकिन वह बैठक इस कमरे तक ही सीमित रहती है और परिणाम आज भी यही है कि शहर के सभी मार्गो चौराहा पर जाम ही जाम दिखाई देता है। इस समय सबसे बड़ी समस्या शहर के अधि ाकतर मार्गो मोहल्ले व कॉलोनियों की गलियों मैं सिविल लाइन बिछाने के लिए गड्ढे तो खुद दिए जाते हैं लेकिन उसे वैसा ही छोड़ दिया जाता है और आने वाले दिनों में खासकर बारिश के दौरान यहां पर रह रहे स्थानीय लोगों के अलावा इधर से गुजरने वाले लोगों को भी काफी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा।इसी तरह कई समस्याएं रामनगरी में है परंतु इन गंभीर समस्याओं पर संबंधि ात विभाग चुप्पी साधे है जिसके चलते स्थानीय लोगों में उनके अधिकारियों कर्मचारियों के प्रति आक्रोश प्राप्त है।

घरों के सामने गंदा पानी इकट्ठा होने से बछड़ा सुलतानपुर वासियो में आक्रोश

अयोध्या।नगर निगम जहां 31 तारीख को सामूहिक स्वच्छता का इतिहास लिखने के लिए जोर–शोर से तैयारी में जुटा है लेकिन बछड़ा सुलतानपुर में स्थित तालाब के गंदे जल के जल भराव से नगर निगम वहां के लोगों को निजात नहीं दिला पा रहा है।जिसके चलते वहां के स्थानीय लोगों में नगर निगम सपा पार्षद के अलावा नगर निगम के महापौर आयुक्त तथा अन्य कर्मचारियों के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। यहां के लोगों का कहना है कि यहां पर साल भर सबसे बड़ी समस्या वहां पर स्थित तालाब के गंदे पानी को लेकर है। लोगों का मानना है कि यह गंदा पानी नाली से ऊपर होकर सड़क तथा आसपास के मकान में भी जा रहा है और बारिश की छोड़िए साल भर यहां पर जल भराव की स्थिति बनी रहती है। लोगों ने बताया जबकि इधर से बैंकर्स कॉलोनी को जाने वाला मुख्य मार्ग भी है जो देवकाली रीडगंज से बछड़ा सुलतानपुर होते हुए अमानीगंज को यह संपर्क मार्ग मिलता है जिसके चलते इधर से सुबह से लेकर देर रात तक लोगों

का आवागमन भी बना रहता है वहीं पर अस्पताल तथा मंदिर भी है इससे भी यहां पर मरीजों तथा श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है जो मजबूरी में सड़क पर बहने वाले गंदे जल के बीच से होकर गुजरते हैं। इसके अलावा बछड़ा सुलतानपुर से देवकली बेनीगंज संपर्क मार्ग के बीच पर भी जल भराव साल भर बना रहता है इधर से गुजरने वाले लोग भी मजबूरी में इस गंदे पानी से होकर ही आते जाते हैं। लोगों ने बताया कि इसकी शिकायत स्थानीय पार्षद के साथ–साथ महापौर नगर आयुक्त तथा अन्य नगर निगम के कर्मचारियों से लिखित तथा मौखिक रूप से किया गया लेकिन स्थिति वैसे ही बनी है। वहां के लोगों का कहना है जब बिना बरसात के हम सभी लोगों के सामने सड़कों तथ घरों में गंदे पानी का भराव है तो बारिश में और भी दिक्कत रहती है। यहां के स्थानीय लोगों ने कहा कि अगर इस गंभीर समस्या पर नगर निगम ध्यान नहीं देता है तो आने वाले दिनों में सभी लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे।

थाना साइबर क्राइम टीम ने लौटाये 88000ध्– रुपये की धनराशि

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।इस समय एसपी ग्रामीण ध्नोडल अधिकारी साइबर क्राइम एवं सीओ साइबर क्राइम के नेतृत्व में साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाया जा रहा है। वही कई पीड़ितों का पैसा भी साइबर टीम द्वारा वापस कराया जा रहा है।सोमवार को प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम मोहम्मद अरशद ने इसी क्रम में लोगो को जागरुक करते हुए थाना साइबर क्राइम जनपद–अयोध या के एनसीआरपी पोर्टल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा धोखे से आवेदक का मोबाइल हैक कर साइबर ठगी कर लेने के क्रम मे त्वरित कार्यवाही करते हुए आवेदक का 88000ध्– रुपये की धनराशि को वापस कराया गया।

रात मे आघोषित विद्युत कटौती से आम जनमानस परेशान

अयोध्या।शहर के कई इलाको मे अघोषित विद्युत कटौती के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।इस समय सबसे अधिक शहर वासियों को रात मे विद्युत कटौती के चलते हो रही है।वहीं जहां पर रात में लाइट रहती भी है तो लो वोल्टेज होने की चलते एसी तो छोड़िए कूलर और पंखे भी ना के बराबर ही चलते है। जिसके चलते इन लोगों को पूरी रात जागकर बिताने को मजबूर है।भीषण गर्मी में वह भी रात में आघोषित विद्युत कटौती के चलते लोगों का बुरा हाल है। देखा जाए तो यह कटौती शाम होते ही शहर के कई इलाकों में शुरू हो जाती है और भर तक इसकी लुका छुपी जारी रहती है।जिसके चलते लोगों को पूरी रात जाग कर बितानी पड़ रही है। शहर के लालबाग,देवकाली चौक,नाका,अमानीगंज सहित अन्य विद्युत उपकेंद्रों पर यह गंभीर समस्या देखी जा सकती है।यहाँ से अन्य मोहल्लों तथा कॉलोनियों में विद्युत सप्लाई सुचारु रूप से नहीं हो पा रही है।अगर हो भी रही है तो लो वोल्टेज।जिसके चलते एसी, कूलर,पंखे, फ्रिज सहित अन्य बिजली से चलने वाले उपकरण लो वोल्टेज के कारण ठीक से नहीं चल रहे है।

महापौर और नगर आयुक्त की संवेदनशील पहल ने नौतपा में राहगीरों को दी राहत

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या। शहर की सड़कों पर नौतपा की तपिश कहर बनकर उतर रही है। तापमान 43 डिग्री के पार है और चिलचिलाती धूप में हर चौराहा मानो आग उगल रहा है। ऐसे कठिन समय में रिकाबगंज चौराहे पर नगर निगम द्वारा लगाया गया ग्रीन नेट सिर्फ छांव नहीं, बल्कि संवेदनशील

प्रशासन की जीवंत तस्वीर बन गया है। महापौर और नगर आयुक्त की पहल पर शुरू हुए इस प्रयास ने यह साबित कर दिया कि जनसेवा केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि आम आदमी की परेशानी को महसूस करने से होती है। रेड लाइट पर रुकने वाले राहगीरों, बाइक सवारों और ट्रैफिक कर्मियों के लिए यह छोटी–सी व्यवस्था बड़ी राहत बनकर सामने आई है। लोगो के शब्दों में कहें तो एक अच्छा शहर वही होता है, जहां प्रशासन जनता की धूप को भी अपनी जिम्मेदारी समझे। अयोध्या नगर निगम की यह पहल वास्तव में प्रशंसा की हकदार है।

गंगा दशहरा के दृष्टिगत डीएम-एसएसपी ने किया सरयू घाटों का निरीक्षण

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।गंगा दशहरा पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित बनाए रखने हेतु जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर ने सरयू घाटों एवं राम की पैड़ी का स्थलीय निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने घाटों पर साफ–सफाई, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, पेयजल, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन तथा श्रद्धालुओं के आवागमन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि गंगा दशहरा के अवसर पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित कर ली जाएं।इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी निगरानी एवं भीड़ प्रबंधन के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।जिलाधिकारी ने नगर निगम एवं संबंधित विभागों को घाटों पर निरंतर सफाई व्यवस्था बनाए रखने तथा जलभराव एवं फिसलन जैसी समस्याओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही श्रद्धालुओं से अपील की कि वे प्रशासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का पालन करें एवं पर्व को शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ वातावरण में संपन्न कराने में सहयोग करें।इस अवसर पर नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार, एसपी नगर चक्रमणि त्रिपाठी,अपर जिला अधिकारी (नगर) योगानंद पांडे सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रभारी मंत्री एवं विधायकों से मिला पीड़ित परिवार, कुमारगंज पुलिस की हुई शिकायत

अयोध्या।कुमारगंज थाना क्षेत्र में हिस्ट्रीशीटर अपराधी एवं उसके साथियों द्वारा एक ब्राह्मण परिवार के घर पर चढ़कर तोड़फोड़ करते हुए महिला, बच्चों एवं परिवार के लोगों की बर्बरता पूर्वक पिटाई किए जाने के मामले में कुमारगंज पुलिस द्वारा एसएसपी के आदेश के बावजूद भी मुकदमा न दर्ज किए जाने की शिकायत जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही सहित विध ायकों अमित सिंह चौहान चंद्रभानु पासवान एवं पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू से से हुई।जहां पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा दिलाते हुए अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही किए जाने की बात कही गई है। बताते चले कि कुमारगंज थाना क्षेत्र के उधुई पूरे विन्धा पाण्डेय पुरवा गांव निवासी शीतला प्रसाद पाण्डेय ने देकर आरोप लगाया था कि घर में तोड़फोड़ मारपीट और जान से मारने की धमकी के बावजूद कुमारगंज पुलिस ने अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। पीड़ित शीतला प्रसाद पाण्डेय के अनुसार बीते 21 मई की शाम करीब 5 बजे वह अपने घर पर बैठकर भोजन कर रहे थे। तभी खण्डासा थाना क्षेत्र के अंजरौली पूरे बेड़ियन का गांव निवासी हिस्ट्रीशीटर अपराधी रोहन पुत्र राजू, रोशन सिंह, अनमोल तथा तीन–चार अज्ञात लोग उनके घर पहुंचे और गाली–गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि जान बचाने के लिए वह घर के अंदर भागे तो हमलावर वहां भी पहुंच गए इससे भी जी नहीं भरा तो उन्होंनेपीड़ित परिवार के घर जमकर तोड़फोड़ भी की। बीच–बचाव करने आई उनकी पत्नी और बेटे को भी जमकर पीटा। जाते समय आरोपियों ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद पीड़ित ने कुमारगंज थाने में लिखित शिकायत दी, लेकिन आरोप है कि थाने के उपनिरीक्षक नूतन स्वरूप व हिस्ट्रीशीटर रोहन सिंह के गहरे संबंधों के नाते पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद शीतला प्रसाद अपनी पत्नी और बेटे के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित का कहना है कि एसएसपी ने उन्हें थाने जाकर मुकदमा दर्ज कराने का आश्वासन दिया था।पीडित परिवार जब दोबारा कुमारगंज थाने पहुंचा तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने कहा कि "बड़े साहब छुट्टी पर हैं, उनके आने के बाद ही कार्रवाई होगी।" हालांकि पुलिस ने पीड़ित परिवार के चोटहिल लोगों का मेडिकल परीक्षण भी करा लिया है। कुमारगंज पुलिस की करतूत से तंग आकर कृषि विश्वविद्यालय सभागार में आयोजित भाजपा के दो दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन करने पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही एवं विधायकों से मिलने पीड़ित परिवार पहुंच गया। पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी और खब्बू तिवारी एवं मिल्कीपुर विधायक चंद्रभानु पासवान तथा बीकापुर विध ायक अमित सिंह चौहान ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर से थाने के उप निरीक्षक नूतन स्वरूप की शिकायत करते हुए तत्काल उनका स्थानांतरण थाना कुमारगंज से अलग करने एवं मामले में हिस्ट्रीशीटर अपराधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए प्रभावी कार्यवाही किए जाने की बात कही।

भाजपा का दो दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग शुरू

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान–2026 के अंतर्गत दो दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ रविवार को किया गया।यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज स्थित पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय के ऑडिटोरियम हाल में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में जिले भर से भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि ा और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए।यह प्रशिक्षण वर्ग कुल 11 सत्रों में संपन्न कराया जाना है, जिसमें कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारध ारा, संगठनात्मक संरचना, कार्यपद्धति तथा जनसंपर्क से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन को अधि ाक मजबूत, सक्रिय और वैचारिक रूप से सशक्त बनाना बताया गया।प्रशिक्षण वर्ग के प्रथम दिन प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया।अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कार्यकर्ता आधारित संगठन है और कार्यकर्ता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत हैं।उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण वर्ग कार्यकर्ताओं के वैचारिक विकास और संगठनात्मक दक्षता बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। पहले दिन चार सत्रों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संगठन की कार्यशैली, पार्टी के सिद्धांतों, कार्यकर्ता की भूमिका तथा संगठनात्मक मजबूती से जुड़े विषयों पर जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान कार्यकर्ताओं को व्यवहारिक और वैचारिक दोनों स्तरों पर प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि वे संगठन की नीतियों को जन–जन तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सकें।भाजपा जिला अध्यक्ष राध ेश्याम त्यागी ने बताया कि प्रशिक्षण वर्ग का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को वैचारिक तथा व्यवहारिक रूप से दक्ष बनाना है। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 26 मई तक चलेगा, जिसमें विभिन्न विषय विशेषज्ञों एवं वरिष्ठ नेताओं द्वारा अलग–अलग सत्रों के माध्यम से मार्गदर्शन दिया जाएगा। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष राधेश्याम त्यागी, जिला प्रशिक्षण वर्ग प्रभारी दिनेश तिवारी, रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, बीकापुर विधायक अमित सिंह चौहान, मिल्कीपुर विधायक चंद्रभानु पासवान, गोसाईगंज के पूर्व विधायक इन्द्रप्रताप तिवारी उर्फ खब्बू, पूर्व जिलाध्यक्ष अवध ेश पाण्डेय बादल, चंद्रबली सिंह, कमलाशंकर पाण्डेय, जिला महामंत्री राघवेंद्र पाण्डेय, अशोक कसौधन, जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार पाण्डेय खुन्नू, अखण्ड सिंह डिम्पल, सुमन पासवान, क्षेत्रीय कार्यालय प्रभारी अखिलेश त्रिपाठी, मीडिया प्रभारी सुशील मिश्रा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कुशाग्र राव ने ताइक्वांडो में जीता स्वर्ण, एसपी चारू निगम ने किया सम्मानित

सुलतानपुर, (संवाददाता)। युवा खिलाड़ी कुशाग्र राव ने सीआईएससीई जोनल गेम्स एंड स्पोर्ट्स 2026 की ताइक्वांडो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता 18 से 20 मई तक लखनऊ पब्लिक कॉलेज, ए–ब्लॉक राजाजीपुरम में आयोजित हुई थी। कुशाग्र ने अंडर–14 वर्ग के 35 से 38 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम स्थान हासिल कर जिले का गौरव बढ़ाया। अमीना ताइक्वांडो अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कुशाग्र राव को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सीआईएससीई की ओर से सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रदान कर सम्मानित किया गया। उनकी इस सफलता से खेल प्रेमियों और अकादमी से जुड़े लोगों में खुशी का माहौल है। शुक्रवार को सुलतानपुर की पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने कुशाग्र राव को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेलों में अनुशासन, मेहनत और समर्पण ही सफलता की असली कुंजी हैं। उन्होंने कुशाग्र की प्रतिभा और मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे खिलाड़ी जिले का नाम प्रदेश और देश स्तर पर रोशन करते हैं। एसपी चारू निगम ने कुशाग्र की प्रशिक्षिका अमीना बानो के प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि किसी भी खिलाड़ी की सफलता के पीछे प्रशिक्षकों की मेहनत और सही दिशा–निर्देशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में सहायक बनती है। अमीना ताइक्वांडो अकादमी के अध्यक्ष शिवकुमार सिंह, उपाध यक्ष डॉ. सुधाकर सिंह, कोषाध्यक्ष एडवोकेट मदन सिंह तथा सदस्य कांति सिंह ने भी कुशाग्र राव की उपलब्धि पर खुशी जताई। उन्होंने प्रशिक्षिका अमीना बानो और कुशाग्र के माता–पिता को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह सफलता जिले के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है।

जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित दो बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन

सुलतानपुर, (संवाददाता)। व्यायु स्वास्थ्य केन्द्र दोस्तपुर में अधीक्षक डॉ अजीत सिंह की अध्यक्षता में संचालित आर.बी.एस.के. टीम द्वारा जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित दो बच्चों की पहचान कर उनका निःशुल्क ऑपरेशन कराया गया। आर.बी.एस.के. टीम में शामिल डॉ रेशमा, डॉ प्रीती सिंह, फार्मासिस्ट विवेक तिवारी एवं फार्मासिस्ट अरविन्द यादव द्वारा बच्चों के परीक्षण के दौरान दोनों बच्चों में जन्मजात हृदय रोग के लक्षण पाए गए थे। इसके बाद टीम ने आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर बच्चों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराया। समय रहते जांच और उपचार मिलने से दोनों बच्चों का सफलतापूर्वक निःशुल्क ऑपरेशन कराया गया, जिससे परिजनों ने राहत की सांस ली। इस अवसर पर अधीक्षक डॉ अजीत सिंह ने कहा कि आर.बी.एस.के. योजना के माध्यम से बच्चों में गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान कर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

गोरखपुर, (संवाददाता)। रसोई गैस सिलिंडर की किल्लत अभी भी बरकरार है। ऊपर से वितरण में अनियमितताओं ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ऐसे में अब प्रशासन भी सख्त हो गया है। वितरण व होम डिलीवरी में अनियमितता मिलने पर ट्रांसपोर्टनगर स्थित गंगा एजेंसी पर 33 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस कार्रवाई के बाद एजेंसी ने सबक लेते हुए होम डिलीवरी का बोर्ड लगा दिया है। उध ार, शुक्रवार को कई एजेंसियों के गोदामों पर ताला लगा रहा। गंगा गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं के मच्छरदानी में रातभर इंतजार करने का भी आरोप है। बीपीसीएल (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) की ओर से जुर्माना लगाए जाने पर हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा कि जबसे गैस संकट शुरू हुआ तबसे गंगा एजेंसी पर सिलिंडर लेने के लिए लंबी–लंबी लाइनें लग रही थीं। गैस सिलिंडर वितरण में अनियमितता और कालाबाजारी में सिलिंडर बेचने की शिकायतें भी लगातार आ सामने आ रही थीं। महिलाएं, बुजुर्ग और दूर–दराज से आने वाले लोग इस अव्यवस्था से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। उपभोक्ताओं को यह कहकर लौटा दिया जाता था कि गैस खत्म हो गई है या स्टॉक उपलब्ध नहीं है। उपभोक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार का आरोप भी लगा। सूत्रों के अनुसार, इसकी जांच बीपीसीएल ऑयल कंपनी के अधिकारी काफी दिनों से कर रहे थे। इसी क्रम में एजेंसी पर मच्छरदानी लगाकर उपभोक्ताओं के रातभर इंतजार करने का मामला सामने आया तो दो दिन में ही गैस एजेंसी पर कार्रवाई हो गई। उपभोक्ताओं को परेशान करने और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ अब कठोर कदम उठाए जाएंगे। गंगा गैस एजेंसी पर सिलिंडर वितरण में अनियमितता मिलने पर जुर्माना लगाकर कार्रवाई की गई है। हिदायत दी गई है कि उपभोक्ताओं को किसी तरह से परेशान न किया जाए।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।